float GDR issues with the restriction that the issue proceeds shall not be deployed in stock markets and real estate sector.

Giving Raw Deal to Urdu and Urdu Programmes in All India Radio and Doordarshan

977. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING
be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Urdu, Urdu Programmes and Urdu staff are being given a raw deal in AIR and Doordarshan;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to improve the conditions for Urdu, Urdu Programmes and Urdu staff in AIR and Doordarshan?

THE MINISTER OF INFORMA-TION AND BROADCASTING (SHRI CM. IBRAHIM): (*) No, Sir.

(b) Does not arise,

(e) Improvement in the quality of programmes of All India Radio and Doordar-(than is a continuing process,

बौद्ध सरकिट योजना

978. श्री भगेन्द्र भाथ ओझा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में बौद्ध धार्मिक-स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कुछ अन्य देशों की सहायता से बौद्ध सरकिट योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से बौद्ध धार्मिक-स्थलों पर इस प्रकार की योजनाएं अभी चल रही हैं; और

(ग) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय हुई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित करने सहित आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए दिसम्बर 1988 में जापान के आर्थिक सहायता कोष (ओ ई सी एफ) के साथ एक आसान ऋण करार किया है। इसकी वित्तीय सहायता 7.76 बिलियन जापानी येन है।

उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा और श्रावस्ती तथा बिहार में बोधगया, नालन्दा, राजगीर एवं वैशाली स्थलों को अभिनिर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को सुदृढ़ करना, स्थानीय सड़कों का सुधार भू-दृश्यांकन जल और विद्युत आपूर्ति का विकास करना, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं।

इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाला सम्पूर्ण कार्य प्रगति पर है।

(ग) विदेशी आर्थिक सहायता कोष ऋण अग्रिम रूप से उपलब्ध नहीं है। कार्यान्वयन अभिकरण तथा राज्य सरकारों को पहले अपने संसाधनों से व्यय करना पड़ता है और बाद में विदेशी आर्थिक सहायता कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है। विदेशी आर्थिक सहायता कोष द्वारा 45.85 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में परियोजना के लिए और 43.60 करोड़ रुपए बिहार परियोजना के लिए पहले ही प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

Realisation from Deep Discount Bonds

979, SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to
state;

(a) the total realisation during 1993-94, 1994-93 and 1995-96 (ram the deep dis count bonds Issued by a number of public financial Institutions;

(b) the loss of potential revenue In these years because of the provisions of lax exemption approved for investment in these bonds; and (c) the effective annual rate of interest reflected in these bonds?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Industrial Development Bank of India (IDBI) and Industrial Finance Corporation of India Ltd. (IFCI) have re-